

समानता

①

अवधारणा एवं अर्थ :-

यद्यपि प्राचीन काल के ही समानता के सिद्धांत का स्वरूप
की अवधारणा उसी लोकप्रियता प्राप्त नहीं हो सकी। पिछली शताब्दी के
समानता की धारणा का उदय 1776 के अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा एवं
1789 की फ्रांसीसी राज्य-क्रान्ति की घोषणा के परिणामस्वरूप हुआ।
"We hold these truths to be self-evident that all men are born equal in the respect of their rights."
"Men are born equal and always continue free and equal in the respect of their rights."

प्राचीन काल के बाद ही लोकतंत्र के प्रचार एवं विकास
समानता की अवधारणा की उत्पत्ति लोकतंत्र होने लगी। किंतु
समाजवादियों को भी अधिक समानता का नारा सर्वप्रथम समाजवाद की
जो शक्तिमान्ता समानता निरर्थक है।

यहाँ तक समानता का अर्थ का प्रश्न है, समानता या समानता
तथा प्रकृतिक न उन्हें समान रख के लिए ही उत्पन्न किया है। इस लक्ष्य
के साथ एक सावधान होना चाहिए। परन्तु इस प्रकार की पूर्ण समानता की
संयोजन करना साम्भव है। किन्ती न ही प्रकृतिक पूर्ण समानता की
होती है। सतह समतल नहीं है। सच्ची उन्नी प्रकार की पूर्ण समानता
नहीं है। यदि ही न ही सच्ची उन्नी प्रकार की पूर्ण समानता सम्भव
के विशेषाधिकार का अभाव है तथा लक्ष्य के लिए समान रूप से पर्याप्त
सुखसुविधा का उपलब्ध होना होगा है। समानता का तात्पर्य किसी भी प्रकार
लक्ष्य है। - समानता का वास्तविक अर्थ यह है कि सभी व्यक्तियों के
अपने विकास के लिए समान सुखसुविधा मिले। राज्य सभी नागरिकों
जन्म, सम्पत्ति, जाति, धर्म, रंग आदि के आधार पर किसी प्रकार
का भेद-भाव-क्रिया विना उन्नी उद्दिष्ट एवं-व्यक्तिगत के पूर्ण
विकास के लिए समानता एवं समान अवसर प्रदान करे। साथ
ही सभी व्यक्तियों को विना किसी भेद-भाव के समान कार्य के लिए
समान वेतन मिले।

समानता की कानूनी अवधारणा :-

कानूनी समानता का दो अर्थ हैं -

① कानून के समान समानता ② कानून का समान संरक्षण। भारतीय संविधान
में भी यह प्रावधान है कि "The State shall not deny to any person
equality before law or the equal protection of law within the
territory of India."

यहाँ मजदूर कानूनी समानता का सामान्य अर्थ यह है कि सभी
नागरिक कानून के समान समान हैं। उनके बीच कानून के द्वारा किसी भी
प्रकार का भेद-भाव नहीं किया जाएगा।

यहाँ के भी समानता की कानूनी अवधारणा की विषय एवं स्पष्ट विवेचना निम्न
① कानून के समान समानता - वास्तव में यह सिद्धांत किन्हीं-सामान्य विधि
के कानून का समान संरक्षण - वास्तव में यह सिद्धांत अमेरिकी संविधान की

यह लिखत कानूनी अधिकार का लाकारकन पहलू है।

श्री देन है प्रथम लिखत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से न्यायालय की सहायता है। अर्थात् कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने एक निर्णय में कहा कि कानून के प्रयोग के किसी प्रकार का स्वैच्छाचारी भेद-भाव-भय नहीं होना ही कानून द्वारा समान संरक्षण है। "सर्वोच्च न्यायालय के एक अन्य निर्णय के अनुसार" कानून के समान संरक्षण के अनुसार का अर्थ यह है कि कानून समान प्रकृति के हो तथा उनका प्रभाव समान ही हो और विधि-निर्माण हेतु राज्य का शक्तियों अथवा पद-भय तथा पराक्रम ज्ञान का अधिकार नहीं। अर्थात् कानून के समान समानता का तात्पर्य व्यक्तियों की पूर्ण समानता नहीं है। अर्थात् इसका अर्थ यह है कि जन्म, जाति या अन्य समान कारणों के आधार पर किसी व्यक्ति को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होगा। और किसी उदाहरण के लिए- स्त्रियों, बच्चों, अपाहिजों अथवा विधवाओं के लिए विशेष प्रकार के कानून बनाए जा सकते हैं। किसी भी पद पर आवेदन व्यक्ति देश के सामान्य न्यायालयों के अधीन माना जाएगा अर्थात् न्यायालय आभिसूक्त की जाति, जन्म, धर्म, सम्पत्ति अथवा धर्म के आधार पर कोई निर्णय नहीं होगा। यहाँ का निर्धारण कि प्रकार क्रिया आयेगा कि यहाँ का कोई प्रत्येक व्यक्ति के आमदनी के अनुसार पड़े।

यह स्पष्ट है कि कानूनी अधिकारों के उपलब्ध विषय-विधि का देन है। इसका तात्पर्य यह है कि कानून के समान सभी व्यक्ति समान हैं तथा राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक ही कानून बनाएगा और उन्हें एक समान रूप से लागू करेगा। यह लिखत कानूनी अधिकार का नकारकन पहलू है।

यह स्पष्ट है कि कानूनी अधिकारों के उपलब्ध विषय-विधि का देन है। इसका तात्पर्य यह है कि कानून के समान सभी व्यक्ति समान हैं तथा राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक ही कानून बनाएगा और उन्हें एक समान रूप से लागू करेगा। यह लिखत कानूनी अधिकार का नकारकन पहलू है।

राजनीतिक अधिकारों - राजनीतिक समानता लोकतंत्र का मुख्य तत्व है। राजनीतिक समानता का अर्थ प्रायः है कि सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से शासन-कार्य के भाग लेने का अधिकार प्राप्त हो। राज्य के समान रूप से मतदान का अधिकार प्राप्त हो। अर्थात् किसी भेद-द्वारा कुछ शक्ति-शक्ति नहीं रहे। सभी नागरिकों को समान रूप से चुनाव के स्वतंत्रता का अधिकार है। सभी नागरिकों को समान रूप से चुनाव पद प्राप्त करने का अधिकार है। सभी नागरिकों को समान रूप से राजनीतिक विरोध योग्यता के आधार पर इस शक्ति देना अथवा किसी अन्य सहायता है। नागरिकों को प्राथमिक शक्ति देना अथवा किसी अन्य का अधिकार है। तथा सरकार को आलोचना

नी देखें। इस हेतु नागरिकों को विचारों की अभिव्यक्ति तथा दल निर्माण करके का अधिकार प्राप्त होना चाहिए सामाजिक समानता की आवश्यकता

लक्ष्मणसुन्दर की अवधारणा - प्रत्येक नागरिक को समाज की एक ही चाँही समाज के हित, जाति, रंग, लिंग के आधार पर व्यक्तिगत भेद-भाव नहीं किया जाना चाहिए। इस हेतु संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं। संविधान के यह रूप ध्वस्त करके उल्टा किया है कि राज्य किसी नागरिक को विरुद्ध केवल धर्म के आधार पर अलग अलग अतिरिक्त उपयोग की विरुद्ध ही भेद-भाव नहीं करेगा। साथ ही नागरिकों के अधिकार पर भेद-भाव नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त हुआ-दूर को निषिद्ध करने दिया गया है। उपरोक्त किसी भी प्रकार के भेद-भाव के लिए व्यक्ति का अधिकार प्राप्त करने में व्यवस्था है।

यद्यपि भारत के समाज अन्य विकासशील देशों के भी अत्यन्त विभिन्न देशों के प्रत्येक समाजिक क्रिया जा रहा है-किंतु व्यवहार के आज भी उदाहरण के लिए अफ्रीका के निवासी लोगों के साथ देवों को मिलता है। एवं इन्हीं के प्रति भेद-भाव, एवं के यही-देवों के प्रति सामाजिक भेद-भाव के उदाहरण। यद्यपि सामाजिक समानता के अन्तर्गत विरुद्ध प्राप्ति-सुरा के लिए पत्र के अन्तर्गत सामाजिक समानता पर पर्याप्त ध्यान दिया था। दुर्भाग्यवश पिछले वर्षों में हितों के लिए भी अनेक क्रियान्वयन चलाए गए हैं/अन्य यह लक्ष्य है कि सामाजिक समानता को विधान एवं के नीचे लाकर आगे किया गया है किंतु पूर्णतः इस लक्ष्य को प्राप्त अभी-वर्षों हैं।

सामाजिक समानता की अवधारणा - सामाजिक समानता की अवधारणा लक्ष्मणसुन्दर की एवं विरुद्ध देशों की सर्वाधिक लोकप्रिय अवधारणा है-। समाजवादी विचारों में सामाजिक समानता को समी-प्रकार के समाजों की आधार माना है। समाज ने सामाजिक समानता की व्याख्या करते हुए कहा है कि प्रत्येक स्त्री एवं पुरुष को समानता का समान प्रदत्त दिया जाए और सामान्य अर्थ है- समाज के धर्म, जाति, रंग, लिंग के प्रयोग का समाज अधिकार होगा। किंतु व्यक्ति को भौतिक उपायों के अनुसार अधिक समानता का अधिकार यह है कि सामाजिक क्षेत्र के सभी व्यक्तियों को समाज के वित्त दंड दिया जाए। राज्य के हितों को समाज के धर्म का धर्म देकर दे दिया जाए। समाज के अधिक समानता का अर्थ न तो धर्म का धर्म वे वृत्त: मुक्त रहना है। परन्तु इकाई-सही तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को उचित योग्यता एवं क्षमता के अनुसार अधिक उपयोग का अवसर मिले तथा समीको सम्यक् अवसर प्राप्त हो जाए।

सम्पत्ति का केन्द्रिकता ना हो तथा किसी के श्रम का बहुपरियोजना किसी अन्य के श्रम के लिए ना हो

आर्थिक समानता के निम्नलिखित पक्ष हैं -

- प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम आर्थिक आवश्यकता - यथा मोजब वस्त्र, आवास की सुविधा होनी चाहिए।
- प्रत्येक व्यक्ति को होलगा, पर्याप्त मजदूरी एवं शिक्षा के लिए पर्याप्त अवकाश मिलने चाहिए।
- प्रत्येक व्यक्ति को अपनी कार्यक्षमता एवं योग्यता में वृद्धि के लिए पर्याप्त मौलिक साधन, उपकरण तथा रहन-सहन प्राप्त होना चाहिए।
- समाज के समस्त कर्माचारियों के आधार पर दो वर्गों के बहुत आर्थिक विषमता नहीं होनी चाहिए।

समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था होनी चाहिए। बेकारी, दुहावा, बीमारी एवं अन्य असहाय परिस्थितियों के व्यक्तियों को राज्य की ओर से आर्थिक सहायता प्राप्त होनी चाहिए।

अज्ञानता को दूर करने के लिए व्यवस्थाओं को व्यवहार में लाने तथा आर्थिक शिक्षा के माध्यम से आवश्यकताओं एवं उदात्तताओं के अभाव को दूर करना है।

आर्थिक उदात्तता का अर्थ है कि सम्पत्ति का पूर्ण रूप से समाज के सदस्यों के साधनों पर राज्य का पूर्ण स्वामित्व हो। सभी मनुष्य अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे तथा उन्हें आवश्यकता अनुसार वेतन प्राप्त होगा।

आधुनिक उदात्तता का अर्थ है कि राज्य के सम्बन्ध में लोककल्याणकारी नीति का अपना है। राज्य केवल समाज के हित के दृष्टिकोण से ही कार्य करेगा।

आधुनिक उदात्तता का अर्थ है कि समाज के हित के दृष्टिकोण से ही आर्थिक समानता की प्राप्ति का प्रयास किया गया है। समाज के आधार पर मिश्रित आर्थिक व्यवस्था को अपनाया गया है।

आधुनिक उदात्तता का अर्थ है कि समाज के हित के दृष्टिकोण से ही आर्थिक समानता की प्राप्ति का प्रयास किया गया है। समाज के आधार पर मिश्रित आर्थिक व्यवस्था को अपनाया गया है।